



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204]
No. 204]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 1997/ज्येष्ठ 7, 1919
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 1997/JYAISTHA 7, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1997

सा.का. नि. 282 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

(सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1997

भविष्य निधि तथा उपदान से संबंधित मद्रास पोर्ट ट्रस्ट विनियम का अक्रिमण करते हुए महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. लघु शीर्ष :

ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1997 के नाम से कहलाए जाएंगे।

2. अनुप्रयोग :

दिनांक 1-4-1963 को या उसके बाद नियुक्त स्थाई और अस्थाई सभी कर्मचारियों तथा पुनर्नियुक्त पेंशनर्स (सिविल पेंशनर को छोड़कर) और जो एक वर्ष की सेवा समाप्त कर चुके हैं और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सामान्य भविष्य निधि में शामिल किए गए हैं के लिए ये विनियम लागू होंगे।

स्पष्टीकरण :

- (1) इन विनियमों के तहत पर्यवेक्षी को अस्थाई कर्मचारी माना जाएगा।
- (2) अस्थाई कर्मचारी माह के बीच के दौरान एक वर्ष की सेवा समाप्त कर लेता है तो अगले महीने से निधि को अंशदान कर सकता है।
- (3) अस्थाई कर्मचारी (पर्यवेक्षी सहित) जो नियमित रिक्ति में नियुक्त किया गया हो और एक वर्ष से भी अधिक सेवा करने वाला हो तो एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पूर्व ही किसी भी समय अंशदान दे सकता है।

क्षतिपूर्ति भत्ता, समयोपरि यात्रा भत्ता, अन्य सभी भत्ते जिन्हे वेतन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, शामिल नहीं होंगे ।

§ २५६ कर्मचारी - स्थाई तथा अस्थायी कर्मचारी शब्द को जो अर्थ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी नियुक्ति/पदोन्नति आदि, विनियम में दिया गया है वही होगा ।

§ २५७ परिवार से तात्पर्य § ११ पुरुष अंशदाताओं के मामले में, पत्नी या पत्नियाँ, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहने, मृतक पुत्र की विधवा, तथा बच्चे तथा जिस मामले में अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं हो तो दादा-दादी ।

बर्तते कि अगर अंशदाता यह सिद्ध करता है कि उसकी बीबी कानूनी रूप से उससे अलग हो गई है या वह जिस समुदाय की है के सामाजिक रिवाजी नियम के तहत वह अनुरक्षण के लिए हकदार नहीं है तो इस विनियम के सम्बन्ध में वह अंशदाता के परिवार की सदस्य नहीं होगी, जब तक कि अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में उसे परिवार के सदस्य के रूप में मानने के लिए लिखकर नहीं दे देता । तथा

§ २५८ स्त्री अंशदाता के मामले में, पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहने, मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे तथा जिस मामले में अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं हो तो दादा-दादी ।

परन्तु अगर अंशदाता लिखित रूप में लेखा अधिकारी को अपने पति का नाम परिवार से निकालने के लिए देती है तो इस विनियम के सम्बन्ध में पति, किसी भी मामले में अंशदाता के परिवार का सदस्य नहीं होंगे जब तक कि अंशदाता उसे रद्द करने के लिए लिखित रूप में नहीं देती ।

स्पष्टीकरण :

=====

बच्चे से तात्पर्य है वैध बच्चा तथा गोद लिया हुआ बच्चा, जिसका गोद लेना अंगदाता के वैयक्तिक नियम द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो कर्मचारी के साथ रहता हो तथा परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, तथा जिसे कर्मचारी ने विशेष असीयत द्वारा जन्म दिए हुए बच्चे के सम तुल्य स्थान दिया हो ।

§एच§ "निधि" से तात्पर्य मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सामान्य भविष्य निधि से है ।

§आई§ "छुट्टी" से तात्पर्य मद्रास पोर्ट ट्रस्ट छुट्टी विनियम के तहत किसी भी प्रकार की छुट्टी से है ।

§जे§ "स्वीकृतिदाता" से तात्पर्य इन विनियमों के प्रयोजनार्थ इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित के अनुसार होगा ।

§के§ "वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है ।

§2§ इन विनियमों में प्रयोग की गई अन्य कोई व्यक्ति भविष्य निधि अधिनियम 1925 §1925 का 19 वीं में या केन्द्र सरकार की मौलिक नियमावली में या बोर्ड द्वारा बनाए गए अन्य किसी विनियम में जिस अर्थ के लिए बताया गया है, उसी से है ।

4. निधि का गठन तथा प्रबन्धः

=====

§1§ निधि का प्रशासन बोर्ड द्वारा चलाया जाएगा तथा भारत में रुपए के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा ।

§2§ इन विनियमों द्वारा, बोर्ड, लिखित रूप में, संकल्प द्वारा यह निर्धारित करेगा कि इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग स्वीकृतिदाता द्वारा किया जाएगा । ऐसे किन्हीं संकल्पों को संशोधित या निरस्त करने का बोर्ड को अधिकार होगा ।

5. भविष्य निधि आरक्षण निधि :

=====

॥1॥ जब कभी निधि की प्रत्याभूतियाँ पूर्ण होती हैं या बेची जाती हैं, तब बोर्ड निम्न प्रक्रिया अपनाएगा:-

॥ए॥ ऐसे पूर्ण होने या बेचने से कोई लाभ होगा तो उसे भविष्य निधि आरक्षण निधि कहलाए जाने वाली आरक्षण निधि में जमा किया जाएगा ।

॥बी॥ ऐसे पूर्ण होने या बेचने से कोई नुकसान होता है तो "भविष्य निधि आरक्षण निधि" से पूरा किया जाएगा ।

॥2॥ बोर्ड यह भी करेगा कि:-

॥ए॥ अगर जब कभी "भविष्य निधि" आरक्षण निधि में कोई कमी उत्पन्न हुई तो उसे अपने राजस्व लेख से पूरा किया जाएगा ।

॥बी॥ ऐसा उप विनियम के प्रावधानों के तहत होगा ।

॥ती॥ जब कभी यह आरक्षण निधि बंद कर दी जाती है तो उसके राजस्व लेख के अन्तिम शेष को भविष्य निधि आरक्षण निधि में जोड़ा जाएगा ।

नोट: उपरोक्त 1 अप्रैल 1940 से लागू होगा ।

॥3॥ किसी एक समय भविष्य निधि आरक्षण निधि लेख में रखी जाने वाली अधिकतम राशि रूपर 10,000/- ₹रूपर दस हजार₹ होगी । इस सीमा से अधिक आने वाली राशि को राजस्व लेख में जमा के रूप में स्थानान्तरित किया जाएगा ।

6. नामांकन:

=====

॥1॥ अंशदाता निधि में शामिल होते समय निधि में जमा की गई अपनी राशि को अपनी मृत्यु के पहले देय राशि या देय राशि जिसे नहीं लिया गया है, को प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक नामांकन, विभागाध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेजेगा ।

परन्तु नामांकन करते समय अंशदाता का परिवार हो तो नामांकन परिवार सदस्यों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा ।

§2§ उप विनियम §1§ के तहत, अगर अंशदाता एक से अधिक व्यक्ति को नामांकित करता है तो उसकी निधि में जमा राशि की सम्पूर्ण राशि को समाते हुए हरेक नामांति को देय या देय अंश को सूचित करेगा ।

§3§ अनुसूची में बताया अनुसार हरेक नामांकन तैयार किया जाएगा ।

§4§ अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में नामांकन रद्द करने के बारे में सूचित कर सकता है । अंशदाता इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी सचना के साथ या अलग से नया नामांकन भेज सकता है ।

§5§ अंशदाता को नामांकन में यह प्रावधान करना होगा:-

§ए§ किसी विनिर्दिष्ट नामांति के संबंध में अंशदाता से पूर्व मृत्यु के मामले में उस नामांति को प्रदत्त अधिकार नामांकन में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों, अंशदाता के परिवार का व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति हो । इस खण्ड के तहत जहाँ एक या एक से अधिक व्यक्ति को अंशदाता हक दिलाता है तो उसे हरेक व्यक्ति को देय राशि के अंश को निर्धारित करना चाहिए ताकि नामांति को देय सम्पूर्ण राशि को उपयोग किया जा सके ।

§बी§ उसमें आकर्षकता होने पर विनिर्दिष्ट नामांकन अमान्य हो जाएगा ।

पुनः प्रावधान है कि नामांकन देते समय अंशदाता के परिवार में एक ही व्यक्ति है तो उसे नामांकन में यह प्रावधान करना होगा कि उसके परिवार में अन्य सदस्य या सदस्यों के आने के बाद खंड §ए§ के तहत वैकल्पिक नामांति को दिया गया अधिकार अमान्य माना जाएगा ।

6. खंड §२१ के उप विनियम §५ के तहत बताए गए नामांकन में नामित की मृत्यु हो जाने पर उसके लिए कोई विशेष प्रावधान न रहने पर या खण्ड §बी के उप विनियम §५ या उनके प्रावधानों के अनुसार किसी दुर्घटना के कारण कुछ हो जाए तो नामांकन अमान्य हो जाता है तो अंशदाता इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अधिकारी को लिखित रूप में पुराने नामांकन को रद्द करके नया नामांकन भेजेगा ।

7. अंशदाता द्वारा दिए गए प्रत्येक नामांकन और रद्द करने की हरेक सूचना लेखा अधिकारी द्वारा उसको स्वीकार करने के बाद ही मान्य और लागू होगी ।

नोट : इस उप विनियम में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, व्यक्ति या व्यक्तियों में एक कम्पनी या संघ या व्यक्तियों को निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं शामिल होंगे ।

57. अंशदाता का लेखा :

=====

हरेक अंशदाता के नाम एक लेखा खोला जाएगा जिसमें निम्न लिखित दर्शाया जाएगा ।

1. अंशदाता का अंशदान
2. विनियम 12 के तहत प्रदत्त व्याज
3. अंशदान पर विनियम 14 के तहत प्रदत्त बोनस
4. निधि से भुगतान तथा वसूल तथा वापस किये गये सभी आगम ।

8. अंशदान की शर्तें:

=====

§२१ ड्यूटी पर या विदेश सेवा पर रहते जबत हरेक अंशदाता मासिक अंशदान करेगा । निलम्बन की अवधि के दौरान नहीं करेगा ।

वर्षों कि निलम्बन की अवधि के बाद अंशदाता के पुनः छुट्टी पर आने पर उसको यह विकल्प दिया जाएगा कि निलम्बन की अवधि के दौरान बकाया अंशदान को एक किश्त में या किश्तों में दे सकता है, परन्तु वह राशि उस अवधि के लिए अनुमति राशि से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी :

"डाइस नॉन" अवधि के दौरान अंशदाता को अंशदान भरने की आवश्यकता नहीं है।

§बी§ जब अंशदाता को विदेशी सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है या प्रतिनिधुक्ति पर विदेश भेजा जाता है तो, वह निधि के विनियम के तहत उसी रीति से रहेगा मानो कि वह स्थानान्तरित या प्रतिनिधुक्ति पर भेजा हो।

§सी§ कोई भी अंशदाता जो छुट्टी के दौरान या तो छुट्टी वेतन नहीं लेता है या छुट्टी वेतन अर्ध वेतन के समतुल्य या उससे कम है तो अंशदान न देने का विकल्प दे सकता है।

§डी§ छुट्टी पर जाने से पहले अंशदाता लिखित रूप में लेखा अधिकारी को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सूचना देगा कि उपरोक्त, उप खण्ड §सी§ में संदर्भित छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं काटा जाए। समय पर सूचना न देने से अंशदान काटा जाएगा। इस उप विनियम के तहत अंशदाता द्वारा दिया गया कल्प अन्तिम होगा।

§ई§ उपरोक्त §ए§ में बताई गई किसी बात के होते हुए भी अंशदाता जिस माह में सेवा छोड़ देता है, तब निधि में अंशदान नहीं करेगा।

9. अंशदान की दर: =====

अंशदान की राशि अंशदाता द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है, वशर्त कि निम्न लिखित शर्तों से विधेय हो:-

§२॥ उसे पूर्णक में बताई जाएगी ।

§बी॥ बताई गई राशि परिलब्धियों का 6 % से कम नहीं रहनी चाहिए और कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं रहनी चाहिए ।

§सी॥ इस प्रकार निर्धारित अंशदान जो लेखा अधिकारी को एक माह के नोटिस से दिया हो निम्न प्रकार से होगा:-

§1॥ वर्ष में एक बार किसी भी समय कम किया हो ।

§2॥ वर्ष में कभी एक बार बढ़ाया हो ।

§3॥ उपरोक्त बताए अनुसार कम करने तथा बढ़ाने के लिए प्रावधान है कि कम करने वाली राशि खण्ड §बी॥ में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम न हो ।

§4॥ अगर अंशदान की राशि पैसे में आती है तो उसे अगले पूर्णक में बदल दिया जाएगा ।

इस विनियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों की गणना अंशदाता के ड्यूटी पर रहते वक्त मासिक भुगतान की दर से होगी ।

नोट : निलम्बन की अवधि के सम्बन्ध में अंशदाता द्वारा उसकी बहाली की अवधि के लिए उसे स्वीकृत परिलब्धियों को या उसके एक भाग को बकाए के रूप में भुगतान करने के विकल्प को इस विनियम के प्रयोजनार्थ ड्यूटी पर रहते वक्त परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा ।

10. अंशदान की वसूली :

===== देय अंशदान स्थापना वेतन बिल से मासिक रूप में काटे जाएंगे तथा इनको निधि लेखे में जमा के तहत समायोजित किया जाएगा ।

बशर्ते कि सरकार द्वारा निर्गमित स्वायत्त या नियंत्रित निकाया में प्रतिनियुक्ति पर गये हुए अंशदाता के मामले में ऐसे निकाय द्वारा अंशदान वसूल करके लेखा अधिकारी को अर्पित किया जाएगा ।

ऐसी जमा की गई राशि को हर माह के समाप्त होते ही स्थापना वेतन बिल से भविष्य निधि खाते में रखा जाएगा, जिसे लेखा अधिकारी अपने पास रखेगा ।

11. निवेश : =====

निधि के प्रयोजनार्थ तुरन्त न आवश्यक राशि का समय समय पर बोर्ड द्वारा निवेश किया जाएगा तथा बोर्ड के नाम पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 द्वारा प्राधिकृत बंध पत्र में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में या राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थायी जमा में या समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे निवेशों, में रखा जाएगा तथा निधि के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो तो समय समय पर अपने नाम पर रहने वाली प्रत्याभूतियों को बेखर या स्थायी निक्षेप की आपस पर राशि या राशियों को अर्जित करेगा ।

12. निवेशों पर व्याज: =====

§ 8 अंशदाता द्वारा दिये गए सभी अंशदानों पर बोर्ड द्वारा व्याज दिया जाएगा जिसमें वर्ष के दौरान अन्य कोई राशि जमा की गयी हो शामिल है जैसा कि विनियम 13 के तहत बीमा पालिसी या पालिसीज व्याज सहित उसी व्याज दर पर जैसे विनियम 11 के तहत बनाए गए भविष्य निधि निवेशों पर कार्यालयीन पिछले वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा उपार्जित किया जाता है ।

नोट : इस विनियम के प्रयोजनार्थ व्याज की दर को अगले 1/4 प्रतिशत में पूर्णांकित किया जाएगा ।

§ 9 व्याज की गणना निम्न लिखित प्रकार से की जाएगी । लेख को समाप्त करते वक्त एक वर्ष के लिए या कोई लघु अवधि के लिए आवश्यक हरेक अंशदाता के कुल § 8 में को छोड़कर न्यूनतम मासिक शेष को निश्चित किया जाएगा तथा ऐसे कुल पर उपयुक्त दर या दरों पर एक वर्ष या कोई विनियोजित लघु अवधि के लिए एक माह का व्याज लगाया जाएगा ।

इस प्रकार परिकल्पित किए गए व्याज को हर वर्ष की समाप्ति पर मूलधन के साथ या अगर वर्ष के दौरान समाप्त करते हों तो खाते को समाप्त करने पर जोड़ा जाएगा ।

॥बी॥ ऐसा अंशदाता जो मर जाता है या सेवा छोड़ देता है या वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त होता है के मामले में भुगतान करने वाले महीने के पूर्व गामी महीने में या ऐसी राशि भुगतान के लिए देय हो, के बाद के छह माह के समाप्त वाले माह इनमें से जो अवधि कम है, में पिछले वित्तीय माह के लिए निर्धारित उपयुक्त दर पर व्याज का भुगतान किया जाएगा ।

बशर्ते कि उन मामलों में जिन में लेखा अधिकारी वैयक्तिक रूप से सतुष्ट हो कि भुगतान में देरी की वजह अंशदाता के नियंत्रणाधीन परिस्थितियों से परे हो तथा कि उस मामले के प्रशासनिक विलम्ब की पूर्ण जांच करके कार्रवाई ली गई है, तो जिस माह में राशि का भुगतान हो उसके बाद एक वर्ष तक जो भी पहले हो अंशदाता की राशि में व्याज जोड़ा जाएगा ।

ऐसा अंशदाता जिसकी मृत्यु हो जाती है तथा नागमिती के नाबालिग होने से उसके खाते की राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो इस विनियम के तहत राशि के भुगतान तक या अंशदाता की मृत्यु के बाद इस माह तक जो भी पहले हो अंशदाता की राशि में व्याज जोड़ा जाएगा ।

13. बीमा पॉलिसी के प्रति भुगतान : =====

अंशदाता तथा बोर्ड के बीच पारस्परिक सहमति से बीमा पॉलिसी के प्रति भुगतान सिर्फ उन्हीं अंशदाताओं पर लागू होगा जिन्होंने 1.8.1989 से पहले जीवन बीमा पॉलिसी के लिए निधि से वापसी के लिए अनुमति प्राप्त करली हो तथा यह सुविधा 1.8.1969 के बाद वसूली किसी पॉलिसी के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी ।

14. प्रोत्साहन बोनस :

=====

ऐसा अंशदाता जिसने भाविष्य निधि लेख से 1.4.78 तथा 1.4.1979 तथा उसके बाद हर वर्ष 1 अप्रैल से लगातार 5 वर्ष या 3 वर्ष के दौरान कोई वापसी नहीं ली हो तो, उस मामले में वह 31.3.78 तथा 31.3.1979 तथा पूर्वगामी वर्ष की दिनांक 31 मार्च को तथा उसके पश्चात उनके खाते में जमा समस्त शेष पर राशि पर 1 % की दर से बोनस का हकदार होगा ।

नोट :

§1§ 1978-79 के दौरान बोनस दर के भुगतान हेतु 5 वर्ष की अवधि 1.4.74 से 31.3.79 तक तथा उसी प्रकार की अवधि के रूप में होगी ।

§2§ 1.4.79 से गैर वापसी की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है ।

§3§ शब्द "वापसी" से तात्पर्य प्रति देय तथा अप्रतिदेय वापसी दोनों से है । बीमा पॉलिसी के लिए वापसी से अंशदाता इस सुविधा के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा ।

§4§ इस प्रकार परिकल्पित किए गये बोनस को नजदीकी रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा । पचास पैसे को अगले रूपए में माना जाएगा। भाविष्य निधि शेष पर व्याज के अतिरिक्त इसे भी अंशदाता के लेख में जमा किया जाएगा

§5§ लघु अवधि के लिए अंशदाता के अस्थायी निलम्बन अर्थात् छुट्टी पर रहते वक्त या निलम्बनाधीन, इन मामलों में जहाँ भी नियम लागू है को छोड़कर पाँच वर्ष / तीन वर्ष के दौरान अंशदाता द्वारा किए गये अंशदान की निधि पर ही बोनस स्वीकार्य होगा ।

§6§ बोनस की गणना के प्रयोजनार्थ वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है । अगर कोई अंशदाता वर्ष के मध्य निधि में शामिल होता है या सेवा को छोड़ देता है तो शामिल होने का वर्ष तथा सेवा को छोड़ देने के वर्ष को पूरे वर्ष के रूप में माना जाएगा ।

§7§ बोनस की राशि को बोर्ड राजस्व लेख में घटाया जाएगा ।

15. अन्य सेवा से/को स्थानान्तरण :

=====

कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी, रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की सेवा से बोर्ड की सेवा में आता है, और अगर वह निधि का अंशदाता बनता है तो किसी सरकारी, रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की सेवा से बोर्ड की सेवा में आने की तारीख तक वहाँ की भविष्य निधि के खाते में उसकी जमा राशि को स्थानान्तरित किया जाएगा। इस प्रकार स्थानान्तरित राशि पर व्याज लगाया जाएगा।

अगर किसी अंशदाता की सेवा स्थाई रूप से किसी सरकारी, रेलवे प्रशासन या अन्य नियोक्ता की सेवा में स्थानान्तरित की जाती है तो उसके भविष्य निधि लेख के शेष को उसे नकद भुगतान करने के बजाय नये नियोक्ता के पास उसके खाते में स्थानान्तरित किया जाएगा। और उसके बाद ये विनियम उस पर लागू नहीं होंगे।

16. निधि से अग्रिम :

=====

अध्यक्ष के विवेकानुसार अंशदाता की निधि के खाते में व्याज सहित राशि से अस्थायी अग्रिम अंशदाता को दिया जाएगा जो निम्न लिखित शर्तों से विधेय होगा।

§ 16 अग्रिम का भुगतान निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए:

1. बीमारी :

अंशदाता तथा उसके परिवार के सदस्यों या उस पर निर्भर व्यक्ति की बीमारी या पाररोध या अशक्तता के सम्बन्ध में व्यय का भुगतान।

2. वाध्यकर व्यय :

अंशदाता की प्रतिष्ठा के अनुसार वाध्यकर व्यय, जो सामाजिक रीति रिवाज जैसे कि सगाई/शादी, अंतिम संस्कार, धर्मनुष्ठान आदि के लिए अंशदाता के वास्तविक आश्रित व्यक्तियों के लिए उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया हो।

3. शिक्षा:

निम्न लिखित मामलों में अंशदाता तथा उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति की उच्च शिक्षा हेतु उत्पन्न व्यय के लिए उच्च विद्यालय के स्तर के बाद

॥ए॥ उच्च विद्यालय के स्तर के बाद शैक्षिक, तकनीकी, प्राध्यापकी या व्यावसायिक, पाठ्यक्रमों के लिए विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु । तथा

॥बी॥ भारत में उच्च विद्यालय के स्तर के बाद चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विनिर्दिष्टित पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु बशर्ते कि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्षों से कम न हो ।

4. कानूनी :

निम्न लिखित मामलों में अंशदाता द्वारा कानूनी व्यय को पूरा करने हेतु :-

॥ए॥ उसके द्वारा किए गये किसी कार्य के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप के लिए या झूट्टी को निभाते वक्त उसके द्वारा ऐसे किसी कार्य के लिए लगाये गये आरोप के अभिप्राय के विरुद्ध उसे निर्दोष साबित करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आश्रय लेने वाले मामले में, या

॥बी॥ किसी कार्यालयी दुराचारी आरोप के लिए उस पर अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चलाया जाता है, या अंशदाता अपने बचाव के लिए जर्ज हेतु कानूनी पेशाकार की मदद लेता है तो ऐसे मामले में, या

लेकिन निम्न लिखित के लिए कोई अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा :-

॥1॥ कोई ऐसी घटना जिसमें बोर्ड के कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति न हो, और वह कर्मचारी कोर्ट का आश्रय लेता है तो उस मामले में ।

§ 2॥ जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा के मामले में कोई शिकायत करता है या उस पर लगाए गए किसी दण्ड के विरुद्ध बोर्ड के खिलाफ मुकदमा चलाता है तो

5. पुनः निर्माण :

एक बार, बाढ़, आग आदि की वजह से क्षतिग्रस्त अपनी झोपड़ी या घर को पुनः बनाने के प्रति व्यय को पूरा करने ।

6. न विनिर्दिष्ट किए गये किसी भी प्रयोजन हेतु :

विशेष परिस्थिति में संबंधित अंशदाता जो इन विनियमों में न विनिर्दिष्ट कारण या घोर संकट में होने से अग्रिम की मांग करता है और अगर स्वीकृतिदाता सन्तुष्ट है तो स्वीकृति दे सकता है ।

§ 2॥ अग्रिम के भुगतान हेतु शर्तें :

1. विशेष कारण के सिवाय अन्य कारणों के लिए अग्रिम 3 माह के वेतन से ज्यादा न होगा या अंशदाता की निधि के खाते में जमा शेष राशि, जो भी कम हो वही होगा ।

नोट :

इस विनियम में वेतन से तात्पर्य विनियम 3 के तहत परिभाषित परिलब्धियों से है ।

2. विशेष कारणों को छोड़कर पिछले सब अग्रिमों की अन्तिम वापसी के कम से कम 12 महीने के बाद ही अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी ।
3. अगर अग्रिम पिछले अग्रिम की अन्तिम वापसी के समाप्त होने से पहले स्वीकृत किया जाता है तो, पिछले अग्रिम की शेष वापसी को ऐसे स्वीकृत अग्रिम में जोड़ा जाएगा तथा वापसी के लिए किस्त समेकित राशि पर ही निर्धारित की जाएगी ।

17. अग्रिम की वापसी :

§ १६॥ अंशदाता से वसूल किए जाने वाले अग्रिम की संख्या ऐसी बराबर मासिक किश्तों में होनी चाहिए, जैसा अध्याय निर्देश करें, लेकिन ऐसी संख्या 12 से कम न हो, जब तक कि अंशदाता चयन न करें, या किसी भी मामले में 36 से ज्यादा न हो । कोई भी अंशदाता अपने विकल्प पर उपरोक्त विनिर्दिष्ट के वजाय छोटी किस्त में वापसी कर सकता है । हरेक किस्त पूर्ण रूप में होगी । ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए अग्रिम की राशि को बटाया या घटाया जा सकता है ।

§ १७॥ अंशदानों के लिए वसूली विनियम 10 के तहत बताए गए तरीके से की जाएगी तथा यह अग्रिम देने के बाद छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान को छोड़कर ^{अंशदाता} प्राप्त भुगतान वाली पहली परिलब्धियों से की जाएगी । छुट्टी पर रहते वक्त या निर्वाह अनुदान पर रहते वक्त अंशदाता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी तथा अंशदाता को स्वीकृत वेतन से अग्रिम की वसूली को स्वीकृतिदाता द्वारा मूल्यवी किया जा सकता है ।

§ १८॥ अगर अंशदाता द्वारा एक से ज्यादा अग्रिम लिया गया है तो वसूली के प्रयोजन हेतु हरेक को अलग माना जाएगा ।

18. अग्रिम का गलत उपयोग: =====

इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी अगर स्वीकृतिदाता इस बात से तन्तुष्ट है कि विनियम 16 के तहत निधि से जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम लिया गया है का प्रयोग उसी प्रयोजन हेतु नहीं किया गया है तो अंशदाता को उस अग्रिम की राशि को निधि को वापस करना होगा या अगर ऐसा न करने से स्वीकृतिदाता यह आदेश दे सकता है कि अगर अंशदाता छुट्टी पर हो तो भी उसकी परिलब्धियों से एक या ज्यादा मासिक किश्तों में जो 12 से ज्यादा न हो, जिसका निर्धारण स्वीकृतिदाता करेगा, से वसूल किया जाए ।

नोट : इन विनियम में बताए गए शब्द परिलब्धियों में निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है ।

19. अग्रिम पर व्याजः
=====

अंशदाता को दिए गये अग्रिम की कोई भी राशि जो उसके खाते से आऊटस्टैंडिंग अग्रिम के रूप में कुछ समय के लिए नामे डाला गया है, पर कोई व्याज नहीं लगाया जाएगा ।

20. निधि से अन्तिम निकासी :
=====

॥१॥ अंशदाता स्वीकृतिदाता की स्वीकृति से उसके अंशदान की राशि तथा उस पर जो उसके भविष्य निधि लेख में है लगे व्याज से अन्तिम वापसी ले सकता है, बशर्ते कि उसमें बताई गई शर्तों से विधेय हो ।

ए. आवास : अंशदाता की सेवा के दौरान एक या उससे ज्यादा प्रयोजन हेतु, अर्थात्,

॥२॥ उसे रहने के लिए उपयुक्त मकान के निर्माण या प्रापण या बना बनाया प्लॉट के लिए जिसमें स्टेट हाऊसिंग बोर्ड/को ऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी से अर्जित करने के लिए प्रस्तावित साइट का मूल्य भी शामिल है ।

॥३॥ रहने के लिए बनाने या उपयुक्त मकान या बना बनाया प्लॉट के प्रापण हेतु लिए गए ऋण की शेष राशि की वापसी हेतु :

बशर्ते कि अंशदाता के खाते में उसके द्वारा किए गये वास्तविक अंशदानों तथा उस पर लगा व्याज सहित वास्तविक राशि या मकान/प्लॉट जिसमें साइट मूल्य भी शामिल है, का वास्तविक मूल्य, के लिए, लिए गये ऋण की वापसी अगर है तो वह जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा ।

॥४॥ रहने के लिए मकान बनाने हेतु हाउस साइट की खरीदारी या इस प्रयोजन हेतु लिए गये किसी ऋण की वापसी हेतु ।

बशर्ते कि उपरोक्त बताए गए आवेदन की तारीख से 12 महीने के पहले कोई ऋण न लिया गया हो ।

यह भी प्रावधान है कि निकासी करने वाली राशि अंशदाता के खाते में उसके द्वारा किसी किए गए अंशदान तथा उस पर लगी व्याज सहित राशि की आधी राशि से ज्यादा न हो या साइट का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो वह

स्पष्टीकरण:

बिक्री स्थानान्तरण तथा निष्पादन विलेख के सम्बन्ध में उत्पन्न वास्तविक व्यय को साइट मूल्य के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा ।

§डी§ खंड §सी§ के तहत खरीदे गये स्थान पर मकान का निर्माण:-

बशर्ते कि प्रयोजन हेतु निकासी की राशि, व्याज सहित वास्तविक अंशदान की राशि, जो उसके खाते में है से ज्यादा न हो या मकान के निर्माण में लगा वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो वह

§ई§ निधि या अन्य सरकारी स्रोतों की मदद के बिना मालिक होने या अर्जित मकान या प्लॉट के परिवर्तन या परिवर्धन हेतु ।

बशर्ते कि निकासी की राशि, व्याज सहित वास्तविक अंशदान की राशि से ज्यादा न हो या रूपए 10,000/- जो भी कम हो, वह ।

टिप्पणी :

इन विनियमों के तहत निकासियों की मंजूरी करते समय मंजूरी प्राधिकारी को स्वयं निम्न लिखित बातों पर संतुष्ट होना चाहिए कि मकान प्लॉट/स्थान का आकार और मूल्य असंगत नहीं है:-

- §1§ सम्बंधित अंशदाता की प्रतिष्ठा और
- §2§ उसके/की भविष्य निधि लेख में उपलब्ध स्रोत ।
- §3§ वास्तव में राशि, मकान/प्लॉट/साइट खरीदने के प्रयोजन के लिए या उपरोक्त के लिए लिए गये ऋण की वापसी के लिए जैसा भी मामला हो, अपेक्षित है और
- §4§ खरीदे जाने वाले प्रस्तावित मकान/प्लॉट/साइट का पूरा टाइटल अंशदाता प्राप्त करेगा ।

2. खण्ड §२ के उप खण्ड §२ या §३ के तहत निकासी के लिए अनुमति उन मामलों में भी दी जाएगी जहाँ मकान साइट या मकान पत्तनी या पति के नाम पर हो बशर्ते कि वह अंशदाता द्वारा दिये गए नामांकन में भविष्य निधि रकम को प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिती के रूप में हो ।

3. खण्ड §२ का उप खण्ड §२, §डी या §ई के तहत निकासी की मंजूरी केवल तभी दी जाएगी जब कि अंशदाता निर्मित करने वाले मकान का प्लान या उसमें परिवर्तन और परिवर्धन लाना हो तो उस प्लान को प्रस्तुत करेगा बशर्ते कि जहाँ साइट या मकान हो उस मकान का प्लान स्थानीय नगर-पालिका द्वारा अनुमोदित करा लेना चाहिए और केवल प्लान के वास्तविक अनुमोदन लेने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी ।

4. उप खण्ड §२ या §डी के तहत मकान/प्लेट के निर्माण के मामलों में निकासी केवल बराबर किस्तों में ही स्वीकार्य जाएगी । दो से कम नहीं और चार से ज्यादा नहीं, प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त की मंजूरी मकान/प्लेट के निर्माण की प्रगति के आधार पर ही प्राधिकर्ता द्वारा दी जाएगी ।

5. रकम के निकालने के छः महीनों के भीतर मकान का निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए और निर्माण कार्य की शुरुआत की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर समाप्त कर देना चाहिए ।

मंजूरी प्राधिकारी अपने स्त्रविधेक से निर्धारित छः महीने की अवधि को एक साल तक बढ़ा सकता है ।

6. उप खण्ड §बी के तहत मकान/प्लेट को खरीदने या गिरवी से छुड़ाने के प्रयोजन के लिए, लिए गए ऋण की वापसी के लिए पूर्ण तय या अंशतः राशि निकाली जाए तो वह ऋण निकासी के दिन से तीन माह के भीतर परिसमाप्त कर देना चाहिए ।

7. अगर मकान साईट एक मुश्त खरीद पर की जाती है या इस प्रयोजन के लिए पहले ही लिए गए ऋण की वापसी के लिए हो तो निकासी एक ही किस्त में दिया जा सकता है और साईट किस्त पर खरीदे तो किस्तें तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

8. निकासी या निकासी की प्रथम किस्त जैसा भी मामला हो एक महीने की अवधि के भीतर हाऊस साईट खरीद लेनी चाहिए । इस शर्त को पूरा करने के लिए विक्रेता द्वारा जारी की गई रसीद को मंजूरी प्राधिकर्ता को प्रस्तुत करना अपेक्षित है । तथा निकासी/किस्त की राशि को सम्पूर्ण या साईट की खरीद के लिए भुगतान करके उपयोग में लाया गया इसे साक्षित करने के लिए विक्रेता द्वारा जारी की गई रसीद को मंजूरी प्राधिकर्ता को प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

9. भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए कार्य आवास और आपूर्ति मंत्रालय की योजना के तहत या इस मामले में अन्य किसी सरकार से या पोर्ट ट्रस्ट से सहायता पाने के लिए स्वीकारा गया है के तहत अंशदाता जिसने स्वयं अग्रिम प्राप्त किया हो तो ऊपर चर्चित प्रयोजनों के लिए इन विनियमों के तहत अंतिम निकासी की मंजूरी के लिए पात्र होगा ।

परन्तु उपरोक्त योजना के तहत या अन्य सरकारी स्रोतों या पोर्ट ट्रस्ट स्रोतों के तहत निकाले गए अग्रिम के साथ इन विनियमों के तहत निकाली गई राशि दोनों उक्त योजना के तहत समय समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

10. अगर मकान/प्लेट/साईट आदि स्टेट हाऊसिंग बोर्ड/कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाईटीज से प्राप्त करना हो तो निकासी, अंशदान तथा व्याज सहित वास्तविक राशि की मंजूरी दी जाएगी, ताकि,

§ 1§ आबंटित मकान/प्लेट के पहले भुगतान के लिए और

§ 2§ हाऊसिंग बोर्ड को एक मुश्त भुगतान ताकि कर्मचारी सेवा में रहते समय उसके द्वारा देय किस्तों को कम किया जा सके या शेष देय किस्तों को खत्म किया जा सके ।

अगर कर्मचारी अपने निजी स्रोतों से पहले ही एक मुश्त प्रारम्भिक भुगतान कर चुका हो तो देय किस्तों को कम करने या शेष देय किस्तों को समाप्त करने के लिए अंशदाता द्वारा जमा की गई राशि, प्रोदभूत व्याज सहित एक अंतिम निकासी के लिए अनुमत होगा।

11. अगर बताई गई निकासी राशि की सहायता से किए गए अंशदाता द्वारा प्रस्तावित मकान/प्लेट साईट को प्राप्त करके या गिरवी से छुड़ायी गयी जगह कर्मचारी के ड्यूटी स्थान के पास हो या सेवा निवृत्ति के बाद जहाँ वह वास करना चाहता हो।

12. भवन के प्राप्त करने या मकान या साईट को गिरवी से छुड़ाने के लिए ही निकासी अनुमत होगी।

बशर्ते कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी के स्थान के पास या सेवा निवृत्ति के बाद आवास करने वाले स्थान के पास या पहले से ही मकान/साईट नहीं रखा हो।

13. अंशदाता जो उपरोक्त निकासी प्राप्त करता है को एक करार निष्पादित करना होगा और उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपेक्षित और निर्धारित विधि के अनुसार घोषणा करनी होगी।

14. हाऊसिंग के प्रयोजन के लिए इन उप विनियमों के तहत केवल एक ही निकासी के लिए अनुमति होगी।

15. अंशदाता जब तक बोर्ड की सेवा में रहेगा तब तक प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को या उससे पहले मंजूरी प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि मकान/प्लेट/साईट का मालिक बही है और उपरोक्त की लिखित रूप में मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना तीन वर्ष या अन्यथा कोई भी अवधि हो के लिए ट्रांसफर, बिक्री, गिरवी, भेंट, बदलने पट्टे पर देने आदि के जरिए जगह को नहीं बँटा गया हो। अगर अपेक्षित हो तो उसे कर रसीद टाइटल डीड आदि को भी प्रस्तुत करना होगा। मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के पहले तीन वर्ष की अवधि से अधिक अगर मकान का विक्रय या भेंट या किसी के नाम पर बदलना या गिरवी रखना या पट्टे पर दिया है तो निकासी राशि को विनियम 13 के

तहत समय समय पर निर्धारित उचित दर या दरों पर प्रोदभूत व्याज सहित एक फिरत में एक महीने के भीतर वसूल किया जाएगा।

वृत्त के मामले में मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि अंशदाता की परिलब्धियों में से एक मुश्त या मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए अनुसार मासिक किस्तों में रकम को वसूल किया जाएगा ।

§बी§ निम्न लिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए अंशदाता द्वारा 20 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद §अगर खण्डित अधि कोई हो तो मिलाकर§ या उनकी सेवा निवृत्ति की दिनांक के 10 वर्ष पहले के भीतर जो भी पहले हो ।

टिप्पणी: विनियम-2 के तहत सामान्य भावक्य नाथ में शामिल कर्मचारियों के मामले में राज्य या केन्द्र सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वायत्त कॉर्पोरेट बाड़ी के तहत सेवा की हो तो इस विनियम के तहत अन्तिम निकासी के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

§ए§ शिक्षा :

===== निम्न लिखित मामलों में अंशदाता या उनके करीबी वच्चे की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए :-

§1§ हाई स्कूल स्तर से आगे की शिक्षा, भारत से बाहर के लिए अकादमिक तकनीकी व्यावसायिक या वोकेशनल कोर्स ।

§2§ हाई स्कूल स्तर से आगे की शिक्षा भारत के भीतर हो व्यक्तिगत इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशिष्ट कोर्स के लिए हो ।

परन्तु यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।

यह राशि तीन महीने के पेटन की सीमा तक होगी, लेकिन किसी भी कारण से अंशदाता की नाथ में जमा राशि और उस पर अर्जित व्याज से अधिक नहीं होगी ।

निकासी प्रति छः माह में एक से अधिक अनुमत नहीं होगी ।

संबंधित अंशदाता, मंजूरी प्राधिकारी को, निकासी की दिनांक से छः माह के भीतर यह सतुष्ट करेगा कि उसने जिस प्रयोजन हेतु यह राशि ली थी उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया है ।

इस विनियम के उप खण्ड § 1 और § 6 उप विनियम § 2 के प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए भी अगर अंशदाता द्वारा निकाली गई राशि का कुछ अंश छः महीने के भीतर खर्च नहीं हुआ हो तो और आगे के छः महीनों की अवधि में अंशदाता पुनः निकालने का प्रस्ताव रखता है तो वह, उपरोक्त छः महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व लिखित रूप में मंजूरी प्राधिकारी को बताएगा कि प्रस्तावित निकासी में अधिक राशि को समायोजित कर दिया जाए परन्तु, यह अधिक राशि उपयोग में लाई गई राशि से 10 % से अधिक नहीं होनी चाहिए । और छः महीनों की समाप्ति के पूर्व एक महीने के अन्दर और राशि निकालने की कार्यवाही की जाएगी ।

§ बी § सगाई/विवाह :

===== अंशदाता की स्वयं की सगाई/शादी तथा उसके लड़के या लड़कियाँ या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित अन्य कोई महिला/पुरुष रशितेदार का विवाह/सगाई से सम्बंधित खर्च को पूरा करने के लिए ।

निकासी की राशि हरेक विवाह के मामले में अंशदाता के खाते में जो अंशदान जमा है और उस पर प्रोदभूत व्याज या वर्ग-1 और 2 परिलब्धियाँ अपनी आश्रित बेटी/महिला के लिए 10 माह की या बेटा/पुरुष आश्रित के लिए छः महीनों की परिलब्धियाँ जो भी कम हो और अन्यो के मामले में आश्रित बेटी/पुरुष लिए के लिए 10 माह की परिलब्धि या आश्रित बेटा/पुरुष के लिए छः माह की परिलब्धि जो भी कम हो के बराबर होगी ।

टिप्पणी :

§ 1 § इस विनियम के प्रयोजन के लिए "विवाह" शब्द में "सगाई" भी शामिल है ।

§ 2 § "सगाई" और "विवाह" को इस प्रयोजन के लिए अलग अलग माना जाएगा । अंशदाता जो "सगाई" के लिए इस निधि से पैसे निकालता है तो वह "विवाह" के लिए अन्तिम निकासी के लिए भी पात्र होगा ।

- § 3§ अगर लगातार दो या उतले अधिक विवाह कराते है तो हरेक विवाह के लिए ग्राह्य राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि एक की मंजूरी के बाद दूसरी की मंजूरी पृथक पृथक दी गई हो ।
- § 4§ विवाह कराने के वास्तविक महीने के तीन महीने से पहले निकासी के लिए अनुमति नहीं होगी ।
- § 5§ उसी विवाह के मामले में अंशदाता इन विनियमों की शर्तों पर राशि निकालेगा या विनियम 16 के तहत अस्थाई अग्रिम लेगा ।
- § 6§ विवाह हो जाने के एक महीने के भीतर अंशदाता मंजूरी प्राधिकर्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या अगर वह छुट्टी पर हो तो छुट्टी से लौटाने के बाद एक महीने के भीतर रिपोर्ट करेगा कि जिस प्रयोजन हेतु राशि को निकाला गया था का उसी के लिए वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया है ।

§ सी§ बीमारी : =====

अंशदाता या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के लम्बी बीमारी के लिए खर्च को पूरा करने हेतु । निकासी की राशि अंशदाता के खाते में जमा अंशदान और उस पर प्रोदभूत व्याज या 6 महीनों की परिलब्धियाँ जो भी कम हो होगी ।

जिस प्रयोजन के लिए रकम निकाली गयी थी का पूरा पूरा उपयोग कर लिया गया है की रिपोर्ट को निकासी की दिनांक से एक माह के भीतर अंशदाता मंजूरी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

§ सी§ मोटर कार/मोटर साइकल/स्कूटर आदि की खरीद :

अंशदाता 15 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद § जिसमें रक्कावट की अवधि कोई हो तो शामिल है § या अधिवर्षीयता आय के 5 वर्ष पूर्व मोटर कार/मोटर साइकल/स्कूटर की खरीद के लिए या इस प्रयोजन के लिए अंशदाता द्वारा पहले से ही लिए गए ऋण की वापसी के लिए उसे निकासी की अनुमति दी जा सकती है । वशर्त कि :-

- § 1४ मोटर कार खरीदने के लिए अंशदाता का मूल वेतन रूपर 3500/- प्रति माह या उससे अधिक होना चाहिए और मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के मामले में रूपर 1500/- प्रति माह या उससे अधिक होना चाहिए ।
- § 2४ मोटर कार की खरीद के लिए रूपर 50,000/- तक और मोटर साइकिल स्कूटर आदि की खरीद के लिए रूपर 8000/- तक निकासी की सीमा है या अंशदाता के खाते में जमा राशि जो भी कम हो ।
- § 3४ ऐसी निकासी केवल एक ही बार अनुमत है ।
- § 4४ दूसरी मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर की खरीद के लिए निकासी के मामले में, इस योजना के तहत मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर की खरीद के लिए अग्रिम ग्राह्य नहीं होगा ।
- § 5४ राशि की निकासी के एक माह के भीतर मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर खरीद लेनी चाहिए और खरीद के सबूत को मंजूरी प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो विनियम 15 के तहत सम्पूर्ण राशि को निर्धारित व्याज जैसा कि तय किया गया हो दर के साथ वापस करना होगा ।
- § 6४ मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर का पूर्ण स्वामित्व उसी के नाम पद पर है करके बोर्ड की सेवा में अंशदाता जब तक है प्रति वर्ष मंजूरी प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । वह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कार/मोटर साइकिल/स्कूटर को नहीं बेचेगा, गिरवी नहीं रखेगा या ट्रांसफर नहीं करेगा । और अगर वह निकासी की राशि से विमुक्त किया गया है तो विनियम 12 के तहत निर्धारित उचित व्याज दर के साथ राशि को वापस करके अंशदाता की भविष्य निधि में जमा कर दिया जाएगा ।
- § 7४ ऐसा अंशदाता जो उपरोक्त निकासी को प्राप्त करता है वह निर्धारित स्टाम्प पेपर में मंजूरी प्राधिकारी को वचन देगा ।

§ 10. निकासी :

अंशदाता सेवा निवृत्त होने के 12 महीनों के अन्दर बिना किसी प्रयोजन के जोड़े निधि से उसे देय जमा राशि में से 90 % की राशि तक निकालने के लिए अनुमति दी जा सकती है ।

अन्तिम निकासी के लिए शर्तें :

§ 11. पुनः जमा करना :

इस विनियम के तहत निर्धारित प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक बार कोई भी राशि निकाले और वह अंशदाता द्वारा जिस प्रयोजन हेतु लिया गया था । अधिक हो तो उसे निधि में तुरन्त विनियम 12 के तहत समय समय पर निर्धारित उचित दर या दारों के व्याज सहित पुनः जमा कर देना चाहिए ।

§ 12. वापसी :

अंशदाता जिसे एक या एक से ज्यादा प्रयोजन हेतु निधि से निकासी लेने की अनुमति दी गयी है, को इस विनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि में स्वीकृतिदाता को इस बात से सन्तुष्ट करना होगा कि जिस प्रयोजन हेतु राशि ली है उसका उही प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है तथा अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो इस प्रकार निकासी की गई पूर्ण राशि या जिसके लिए आवेदन किया था उसे उपयोग में नहीं लाया गया तो उतनी राशि का अंशदाता द्वारा निधि में एक किश्त में वापस करना चाहिए तथा ऐसा न करने पर स्वीकृतिदाता यह आदेश देगा कि अंशदाता की परिलब्धियों में से एक किश्त में या ऐसी किश्तों में, जैसा कि स्वीकृतिदाता उचित समझे, से वसूल की जाएगी ।

§ 13

इस विनियम के तहत बताई गई रीति तथा फार्म, जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तथा निर्देशित किया जाएगा, के अनुसार एक या एक से ज्यादा प्रयोजनार्थ निकासी की राशि के लिए अंशदाता को आवश्यक करार, निष्पादन, घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना, तथा उचित रूप से दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए ।

§ 3§ परिवर्तन :

विनियम 16 के तहत किली प्रयोजनार्थ लिए गए अस्थाई अग्रिम के शेष को अंशदाता के लिखित निवेदन पर इस विनियम के तहत अन्तिम निकासी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी निकासी के समय वह उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो ।

21. लेख को बन्द करना तथा भुगतान :

सेवा को छोड़ते समय अंशदाता के खाते को बंद करके उसके खाते के लेख में रहने वाली राशि से काटकर शेष की अदायगी की जाएगी ।

§ 1§ जब बोर्ड की सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है । त्याग पत्र दे देता है ।

बशर्ते कि अंशदाता को सेवा से पदच्युत कर दिया जाए । त्याग पत्र दे दें और अगर अपेक्षित हो तो बोर्ड द्वारा बाद में पुनः सेवा में लेने पर विनियम 12 में प्रावधानित दरों पर ख्याज सहित उसे भुगतान की गई राशि को उसके लेख में जमा करने हेतु लेखा अधिकारी को वापस कर देना चाहिए ।

§ 2§ जब वह अधिवर्षीयता पर सेवा निवृत्त होता है या मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी § सेवा निवृत्ति§ विनियम के तहत निवृत्ति के लिए अनुमति दी जाती है या ट्रस्ट के मुख्य निष्कर्षा अधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है । या

§ 3§ जब उसकी मृत्यु हो जाती है ।

2. अंशदाता की मृत्यु पर भुगतान:

§ 1§ जब अंशदाता का परिवारही तो

§ 1§ अगर अंशदाता ने विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार उसके परिवार से एक या एक से अधिक का नामांकन दिया है तो निधि में उसके खाते में रहने वाली राशि या उसके भाग को नामांकित को या नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार नामांकितों को दिया जाएगा ।

§2§ अगर अंशदाता के परिवार का सदस्य/के सदस्यों के प्रति कोई ऐसा नामांकन नहीं है या अगर ऐसा नामांकन सिर्फ उसकी निधि के खाते की राशि के एक भाग से ही सम्बंधित है तो नामांकन उसके परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने के बावजूद भी उसके खाते की पूरी राशि या उस भाग जो नामांकन से सम्बंधित नहीं हो जो भी माभला हो, को उसके परिवार के सदस्यों के बीच सम रूप में विभाजित की जाएगी ।

बशर्ते कि कोई हिस्सा निम्न लिखित को नहीं दिया जाएगा:-

§1§ कानूनी रूप से वयस्कता प्राप्त लड़का

§2§ मृतक पुत्र का बेटा का जो कानूनी रूप से वयस्कता हो गया हो

§3§ शादीशुदा लड़की जिसका पति जीवित हो, तथा

§4§ मृतक बेटे की शादीशुदा लड़की जिसका पति जीवित हो, अगर खण्ड §1§, §2§, §3§ तथा §4§ में विनिर्दिष्ट के सिवाय उसके अन्य कोई परिवार सदस्य हैं तो वह ।

बशर्ते कि मृतक लड़के की विधवा या विधवाएँ तथा बच्चा या बच्चों के बीच में वह समान हिस्सा ही होगा, जो, अंशदाता के जीवित होने पर लड़के द्वारा प्राप्त किया जाता तथा पहली शर्त के खण्ड §1§ के प्रावधान से छूट दी गई हो ।

टिप्पणी :

§ए§ इन विनियमों के तहत अंशदाता के परिवार के सदस्य को देय कोई भी राशि सिर्फ उसी सदस्य को दी जाएगी जो कि भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा §3§ की उप धारा §2§ के तहत है ।

§बी§ जब अंशदाता का परिवार न हो :

§1§ अगर अंशदाता का परिवार ने किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को विनियम §6§ के प्रावधानों के तहत नामिती बनाया है और वह नामांकन जारी है तो उसकी निधि में जमा राशि अथवा उसका भाग जिससे कि नामांकन संबंधित है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात के हिसाब से उसके नामित/नामिती को देय होगी ।

नोट :

§ 1§ भविष्य निधि अधिनियम 1925 के खण्ड § 1§ की धारा § 2§ में जिसे नामित को अंशदाता के आश्रित के रूप में बताया गया है, ऐसे नामित को ही अधिनियम की धारा 3 की उप धारा § 2§ के तहत राशि दी जाएगी ।

§ 2§ जब अंशदाता का कोई परिवार नहीं हो तथा विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार कोई नामित नहीं दिया गया है या निधि के उसके खाते की राशि के सिर्फ एक हिस्से का नामांकन किया गया है, तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा § 4§ की उप धारा § 1§ का खण्ड § 1§ का खण्ड § 2§ तथा उप खण्ड § 2§ के प्रावधानों के अनुसार पूरी राशि या हिस्सा जिसका नामांकन नहीं किया गया है, पर लागू होगा ।

§ 3§ भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 2 का खण्ड § 1§ में बताए अनुसार जब कोई नामित अंशदाता को आश्रित नहीं हो तो राशि रु. 10000 से कम हो तो उसकी दी जाएगी, और अगर राशि रुपए 10,000/- से ज्यादा है तो वह राशि नामित द्वारा उचित उत्तराधिकार प्रामाण पत्र, प्रोपेट या प्रशासन पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी ।

§ 4§ जब अंशदाता नाबालिग नामित को छोड़ जाता है:

ऐसा मामला जिसमें अंशदाता की मृत्यु हो जाती है तथा उस समय उसका नामितियों में से एक या एक से अधिक नाबालिग है तो उनको भुगतान निम्न प्रकार से होगा :-

§ 5§ नामित § नामितियों को न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक

बशर्ते कि भविष्य निधि राशि रुपए 10,000 तक हो § या पहले रुपए 10,000 अगर भुगतान की राशि रुपए 10,000 से ज्यादा हो तो § नाबालिग की ओर से उसके/उन्के प्राकृतिक अभिभावक या अगर कोई प्राकृतिक अभिभावक उपलब्ध नहीं हो तो अध्यक्ष द्वारा नाबालिग की राशि को प्राप्त करने योग्य चुने गये व्यक्ति को उससे अभिभावकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ही राशि दी जाएगी । नाबालिग/ नाबालिगों की ओर से जो

व्यक्ति राशि प्राप्त करता है, उसको बोर्ड के विरुद्ध कोई अनुवर्ती दावे न देने से सहमत बंध पत्र § दो जमानतों के हस्ताक्षर सहित § देना होगा । रूपर 10,000 से ज्यादा आने वाली शेष राशि को कानून के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

यह भी प्रावधान है कि जिस मामले में प्राकृतिक अभिभावक हिन्दू विधवा या विधुर है, तो उसको उसके नाबालिग बच्चों की ओर से भविष्य निधि राशि का भुगतान, राशि को देखे बिना और अभिभावकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना या अगर जिस मामले में माँ या पिता का हित उस नाबालिग बच्चों के विरुद्ध है, ऐसा ठोस प्रमाण है तो क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

लेकिन यह आवश्यक होगा कि प्राकृतिक अभिभावक की अनुपस्थिति में भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने हेतु पर्याप्त प्रत्यक्ष आधार होना चाहिए । ऐसा आधार तभी माना जाएगा जब वह वास्तविक अभिभावक के रूप में शपथपत्र देगा तथा उसकी नियती सुनिश्चित की गई है । अगर न्यायालय द्वारा अभिभावक को नियुक्त नहीं किया गया है, तथा नाबालिग तथा उसकी सम्पत्ति जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के पास है, कानून के अनुसार वह वास्तविक अभिभावक है । अगर कोई व्यक्ति नाबालिग की ओर से भुगतान का दावा करता है तो उसे शपथ पत्र द्वारा अध्यक्ष को इस बात से सन्तुष्ट करना होगा कि नाबालिग की सम्पत्ति को वह ही सम्भाल रहा है, तथा उसकी देखभाल भी कर रहा है या अगर नाबालिग की भविष्य निधि राशि के सिवाय कोई सम्पत्ति नहीं है तो नाबालिग उसके साथ ही रहता है तथा उसकी देखभाल वह कर रहा है । उपर्युक्त प्रत्याभूति के साथ क्षतिपूर्ति बंध पत्र के अतिरिक्त शपथ पत्र को भी प्रस्तुत करना है । या

§बी§ वयस्क बचने के बाद नामितरी द्वारा दावा करने पर राशि का भुगतान नामितरी को दिया जाएगा ।

बर्षों कि हरेक मामले में विनियम 15 §बी§ की टिप्पणी
14 अनुसार व्याज भुगतान की तारीख तक दी जाएगी या अंशदाता की
मृत्यु के बाद छः माह के समाप्त तक, जो भी पहले हो वह ।

22. राजस्व लेख को जमा :

=====

पूर्ण तीन वित्तीय वर्ष के लिए अदावा किए
गए भाव्य निधि शेष को हर वर्ष के अन्त में बोर्ड के राजस्व लेख में जमा
किया जाएगा ।

इस राजस्व लेख में जमा की गई राशि को अध्यक्ष की
स्वीकृति के बिना, व्यक्ति या व्यक्तियों को जो राजस्व लेख में जमा करने से
इस राशि को ले सकते थे को वापस नहीं की जाएगी ।

23. पॉलिशी की सुपुर्दगी :

=====

§1§ इन विनियमों के तहत अगर उस व्यक्ति को जो पागल
है, कोई राशि या पॉलिशी का भुगतान करना है, सौंपना है, पुनः सौंपना है
या सुपुर्दगी करनी है तो इण्डियन लुनासि अधिनियम 1912 के तहत उसके बदले
में नियुक्ति प्रबंधक को भुगतान या पुनः सौंपने या सुपुर्दगी की जाएगी
न कि उस पागल को ।

§2§ अगर पागल की सम्पदा के लिए कोई प्रबंधक नियुक्त
नहीं किया गया हो तो इण्डियन लुनासि अधिनियम की धारा 95 §1§ की
शर्तों के अनुसार कलेक्टर के आदेशानुसार उस पागल की तरफ से प्रभारी व्यक्ति
को पॉलिशी का भुगतान या पुनः निधरिण किया जाएगा । पागल की तरफ से
नियुक्त उस व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष उतनी ही राशि का भुगतान करेगा
जितना वह उचित समझेगा और शेष राशि या उसके अंश को पागल के परिवार
के ऐसे सदस्यों को जो अनुरक्षण के लिए उस पर आश्रित हैं को भुगतान करेगा ।
लेकिन इन सब को करने के पहले जिस व्यक्ति को राशि देय होगी, इन
विनियमों के तहत माजिस्ट्रेट द्वारा पागल सिद्ध कराने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त
करना होगा ।

24. भुगतान की प्राकृषण :

=====

अंशदाता के खाते में जमी राशि के भुगतान हेतु प्राकृषण बन्ध पत्रों करारों को प्रस्तुत करना, घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना तथा इन विनियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण को प्रस्तुत करना आदि समय समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित रीति फार्म के अनुसार होगा ।

25. व्याख्या :

=====

अगर इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो, उस पर

बोर्ड द्वारा निश्चित होगा ।

26. सरकारी नियमों को लागू करना :

=====

इन विनियमों के प्रावधान तथा इन विनियमों में न आने वाले मामलों को लागू करने में आदेश व सरकारी निर्णय जो सरकारी सामान्य भावश्यक निर्णय {केन्द्रीय सेवाएँ} नियम में हैं को इन विनियमों के औपचारिक संशोधन के रूप में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ अपनाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी व्याख्या तथा संशोधनों का बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्णय लिया गया हो ।

27. निरस्त करना तथा बचत :

=====

भाविष्य निर्णय तथा उपदान से संबंधित मद्रास पोर्ट ट्रस्ट विनियम जो इन विनियमों के लागू होने से पहले थे को इन विनियमों के लागू होते ही निरस्त माने जाएंगे ।

बशर्ते कि निरस्त किए गए विनियमों के तहत किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई या उद्दारीकरण को इन विनियमों के संगत प्रावधानों के तहत बनाया या लिया या लाभ उठाया गया माना जाएगा ।

अनुसूची

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सामान्य भविष्य निधि विनियम के प्रयोजन हेतु मंजूरी प्राधिकारी
=====

विनियम संख्या 3

=====

विनियम प्रत्यायोजित शक्तियों के विवरण प्राधिकारी जिन को
संख्या प्रत्यायोजित शक्तियाँ दी गई हैं

13. जीवन बीमा की पालिसियों पर
प्रीमियम के भुगतान के लिए निधि के
अंशदान को उपरोक्त उपयोग करने हेतु
अनुमति देने के लिए, बोर्ड की भविष्य
निधि के लिए अंशदाता के आवेदन की
मंजूरी के लिए बोर्ड के अधिकारी ।

अध्यक्ष

16. अंशदाता की भविष्य निधि जमा से
अस्थाई अग्रिम की मंजूरी के लिए
बोर्ड के अधिकार ।

अध्यक्ष

विभागाध्यक्ष सहित सभी
कर्मचारियों के मामले में पूरा
अधिकार

उपाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष से इतर सभी
कर्मचारियों के मामले में पूरा
अधिकार

विभागाध्यक्ष

अपने विभाग के वर्ग-1 व 2 और
वर्ग-3 और 4 कर्मचारियों के
मामले में पूरा अधिकार

छूट देने वाले मामलों के लिए उपाध्यक्ष/अध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक है।

- | | |
|--|---|
| <p>20. भविष्य निधि से
अंतिम निकाली</p> | <p>अध्यक्ष; विभागाध्यक्ष तथा
कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार

उपाध्यक्ष: विभागाध्यक्ष से अंतर
कर्मचारियों के मामले में पूरा अधिकार</p> |
| <p>22. राजस्व लेख की जमा जमा से
अर्थात् तीन पूर्ण लेखा वर्षों से
भविष्य निधि में अदाये पड़े
शेष को इन संबंधितों को
भुगतान करने के लिए मंजूर
करने का अधिकार बोर्ड को है ।</p> | <p>अध्यक्ष</p> |

नामांकन प्रपत्र

=====

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सामान्य भविष्य निधि विनियम के विनियम-6

=====

में संदर्भित अनुसूची

=====

लेखा संख्या

में

निम्नलिखित व्यक्ति

जो मेरे परिवार के सदस्य/गैर सदस्य हैं, जैसा कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सामान्य भविष्य निधि विनियम में बताया है को नीचे सूची में मेरी निधि में जमा राशि जो मेरी मृत्यु के बाद देय हो या जो देय हो और न भुगतान किया गया हो को प्राप्त करने के लिए घोषित करता हूँ ।

नामिती	अंशदाता	नामिती	हरेक	आकांक्षितकर्ता	अंशदाता	विनियम 3 में
का नाम	के साथ	की	नामिती	जिनके	की मृत्यु	में बताया अनुसार
और	सम्बन्ध	आयु	को देय	होने पर	हो जाने	नामिती
पूरा			अंश	नामांकन	पर जिस	परिवार
पता				अमान्य	व्यक्ति	का सदस्य
				माना	का	न हो तो
				जाएगा	नामांकन	कारण
					किया	बताएँ
					गया है ।	
					अगर कोई	
					हो तो	
					उसका नाम	
					पता और	
					रिश्ता	

॥ 1 ॥

॥ 2 ॥

॥ 3 ॥

॥ 4 ॥

॥ 5 ॥

॥ 6 ॥

॥ 7 ॥

.....आज के दिनांक को दिन 19 के बजे

अशदाता का हस्ताक्षर

नाम गीटे अक्षरों में

पदनाम

हस्ताक्षर के लिए दो साक्षी

हस्ताक्षर

नाम व पता

1.

2.

लेखा विभाग के उपयोग के लिए

स्वीकृत

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

नामांकन प्रपत्र जारी =====

॥ए॥ आपका नाम भरे

॥बी॥ निधि का नाम पूर्णतः भरे

॥सी॥ निम्न प्रकार से परिवार की व्याख्या है ।

परिवार से तात्पर्य :

=====

॥1॥ पुरुष अंशदाता के मामले में पति या पत्नियाँ, माता पिता, बच्चे, नाबालिक भाई, अविवाहित बहनें, विधवा, बहू, और बच्चे और जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनके पैतृक दादा दादी ।

बशर्ते कि अगर अंशदाता यह साबित करता है कि उसकी पत्नि कानूनी तौर पर अलग हो चुकी है या जिस समुदाय की है, उस समुदाय के कानून के अनुसार हक छीन लिया गया हो और निर्वाह राशि की हकदार है तो इस मामले के लिए इन विनियमों के तहत अंशदाता के परिवार के सदस्य नहीं होगी । अन्यथा अंशदाता, लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा कि वह उक्त के लिए मानी जाएगी ।

॥2॥ महिला अंशदाता के मामले में उसका पति, माता, पिता, बच्चे, नाबालिक भाई, अविवाहित बहनें, विधवा बहू और बच्चे और जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं, उनके पैतृक दादा दादी ।

बशर्ते कि अगर अंशदाता लिखित रूप में लेखा अधिकारी को यह सूचित करती है कि अपने परिवार सूची से उनके पति का नाम हटा दिया जाए तो उनका पति अंशदाता के परिवार का सदस्य नहीं कहलाएगा । परन्तु अंशदाता द्वारा ऐसी सूचना को रद्द करने पर पुनः जोड़ा जाएगा ।

टिप्पणी :
=====

"बच्चा" से तात्पर्य पैदा बच्चे से है और जिसमें गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है । जिसे अंशदाता धैर्यवश से लों द्वारा मान्य बनाता है और यह बच्चा अंशदाता के साथ रहकर उसके परिवार का सदस्य कहलाता है और जिसे कर्मचारी एक पाल द्वारा प्राकृतिक रूप से जन्म लिए हुए बच्चे की हैसियत देता है ।

॥डी॥ स्तम्भ-4 अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन किया जाए तो नामांकी के सामने "पूर्णतः" शब्द लिखना चाहिए । अगर एक से अधिक नामांकन किया जाए तो भविष्य निर्धार की सम्पूर्ण शक्ति को भाग करके प्रत्येक नामांकी के अंश का निर्धारण करना चाहिए ।

॥ई॥ स्तम्भ-5 इस स्तम्भ में नामांतियों की मृत्यु को आकास्मिकता नहीं माना जाएगा ।

॥एफ॥ स्तम्भ-6 अपना नाम सूचित न करें ।

॥जी॥ अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली जगह पर एक लकीर खींच दीजिए ताकि अपने हस्ताक्षर के बाद किसी और नाम को न जोड़ा जा सके ।

[फा. सं. पी. आर-12016/9/96-पीई 1]
के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**(Ports Wing)****NOTIFICATION**

New Dehi, the 27th May, 1997

G.S.R. 282 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust (General Provident Fund) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of Madras Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE**MADRAS PORT TRUST****(GENERAL PROVIDENT FUND) REGULATIONS, 1997**

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Madras Port Trust Board hereby make the following Regulations in supersession of the Madras Port Trust Regulations relating to Provident Fund and Gratuity.

1. Short title :

These regulations may be called the Madras Port Trust (General Provident Fund) Regulations, 1997.

2. APPLICATION :

They shall apply to all permanent and temporary employees and re-employed pensioners (other than Civil pensioners) appointed on or after 1-4-1963 and who have completed one year of service and admitted to the Madras Port Trust General Provident Fund

CLARIFICATION :

(i) A probationer shall be treated as a temporary employee for purpose of this regulation.

(ii) A temporary employee who completes one year of continuous service during middle of a month can subscribe to the Fund from the subsequent month.

(iii) A temporary employee (including Probationers) who has been appointed against a regular vacancy and is likely to continue for more than a year may subscribe to the Fund any time before completion of one year of service

NOTE : A person joining the Trust's service after resigning the service under State or Central Government or Corporate Body owned or controlled by Government may be permitted to contribute to the Fund, provided :

(a) he has already completed one year of service previously in the State or Central Government or Corporate Body owned or controlled by the Government and

(b) If the amount standing to his credit with the previous employer is transferred to the General Provident Fund Account with the Trust

3. DEFINITION :

(1) In these regulations unless the context otherwise requires:

(a) "Accounts officer" means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board or such other officer of the Accounts Department, as may be prescribed by the Chairman.

(b) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

(c) "Board" means the Trustees of the Port of Madras appointed under the Act;

(d) "Chairman" "Deputy Chairman" "Head of Departments" shall have the meaning assigned to them under the Act.

(e) "Emoluments" means save otherwise provided pay, leave salary or subsistence grants as defined in Fundamental Rules of the Central Government or in the Regulations if any framed by the Board whichever may be applicable and such other allowances that may be classified as pay for this purpose from time to time and includes non-practicing allowance granted to Medical Officers in lieu of private practice but does not include conveyance allowance, house rent allowance, city compensatory allowance, overtime and all other allowances not classified as pay.

(f) "Employees" - The word permanent and temporary employee shall have the meaning assigned to them in the "Madras Port Trust Employees (Appointment/Promotions etc.) Regulations".

(g) "Family" means (i) In the case of a male subscriber, the wife or wives, parent, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons' widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent.

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently intimates by express notification in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded; and

(ii) In the case of a female subscriber, the husband, parent, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons' widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent.

Provided that if a subscriber by notification in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

"Explanation" - 'Child' means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber who lives with an employee and treated as a member of the family and to whom the employee has through a special will given the same status as of a natural birth.

(h) "Fund" means the Madras Port Trust General Provident Fund;

(i) "Leave" means any variety of leave under the Madras Port Trust Leave Regulations.

(j) "Sanctioning Authority" for the purpose of these Regulations shall be as prescribed in the schedule attached to this Regulation.

(k) "Year" means a financial year.

(2) Any other expression used in these regulations which is defined either in the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925) or in the fundamental Rules of the Central Government or any other Regulations framed by the Board is used in the sense therein defined.

4. CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF THE FUND:

(1) The Fund shall be administered by the Board and shall be maintained in rupees.

(ii) The Board may, by resolution in writing, prescribe which of the powers conferred upon the Board by these regulations may be exercised by the Sanctioning Authority and may alter or cancel any such Resolution.

5. PROVIDENT FUND RESERVE FUND:

(1) Whenever securities belonging to the Fund mature, or are sold, the Board shall -

(a) Credit to a reserve fund called the 'Provident Fund Reserve Fund' any gain arising on such maturity or by such sale; and

(b) make good from the "Provident Fund Reserve Fund" any loss that may be incurred on such maturity or by such sale.

(2) The Board shall also --

(a) make good from its Revenue account any deficit in the "Provident Fund Reserve Fund" if and when it occurs; and

(b) subject to the Provision of sub-regulation

(3) Pay to the credit of its Revenue Account, the ultimate balance in the 'Provident Fund Reserve Fund' if and when this Reserve Fund is closed.

NOTE: The above will take effect from 1st April, 1940.

3. The maximum amount that can be retained to the credit of the Provident Fund Reserve Fund account at any time shall be Rs.10,000/- (Rupees ten thousand only). Any excess over the limit shall be transferred to the credit of the Revenue Account.

6. NOMINATIONS:

(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer through the Head of Department a nomination, conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Provided that, if at the time of making the nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his/her family.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the form set forth in the schedule.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(5) A subscriber may provide in a nomination --

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his- pre-deceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons, shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he/she shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein:

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he/she shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his/her family.

6. Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under Clause (a) of sub-regulation (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-regulation (5) or the proviso there, the subscriber shall send to the Accounts Officer a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

7. Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, become operative on its acceptance by the Accounts Officer.

NOTE: In this regulation, unless the context otherwise requires, 'Person' or 'Persons' shall include 'a company or association or body of individuals, whether incorporated or not'.

7. SUBSCRIBER'S ACCOUNTS:

An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown:

- i) the subscriber's subscriptions.
- ii) Interest as provided by regulation No. 12
- iii) Bonus as provided under Regulation 14 on subscription.
- iv) All advances paid and recovered and withdrawals from the fund.

8. CONDITIONS OF SUBSCRIPTIONS:

(a) Every subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty or foreign service but not during a period of suspension:

Provided that a subscriber on re-instatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lumpsum or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions permissible for that period.

NOTE: A subscriber need not subscribe during the period treated as 'Dues-non'.

(b) When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the regulations of the fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

(c) A subscriber may at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay.

(d) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in sub-clause (c) above by a written communication to the Accounts Officer through the head of his department before he proceeds on leave. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of subscriber intimated under this sub-regulation shall be final.

(e) Notwithstanding anything contained in (a) above a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service.

9. RATE OF SUBSCRIPTIONS:

The amount of subscriptions shall be fixed by the subscriber himself subject to the following conditions:-

- a) It shall be expressed in whole rupees.
- b) It may be any sum so expressed not less than 6 percent of his emoluments and not more than his total emoluments.
- c) The amount of subscription so fixed by giving a month's notice to the Accounts Officer may be:
 - i) reduced once at any time during the course of the year.
 - ii) enhanced once during the course of the year.
 - iii) reduced and enhanced as aforesaid provided that the amount of subscription so reduced shall not be less than the minimum prescribed in Clause (b)
 - iv) If the amount of subscription payable contain a fraction of a rupee it shall be rounded off to the nearest whole rupee.

Emoluments for the purpose of this regulation shall be calculated at the rate payable to him monthly had he been on duty.

NOTE: Should a subscriber elect to pay arrears of subscriptions in respect of a period of suspension, the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for that period on reinstatement, shall for the purpose of this regulation, be deemed to be emoluments drawn on duty.

10. REALISATION OF SUBSCRIPTIONS:

Subscriptions due shall be deducted monthly from the establishment pay bills and the deductions shall be adjusted to the credit of the Fund Accounts.

Provided that in the case of the subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government, the subscription shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body.

The amounts so credited shall, after the close of each month, be posted in a Provident Fund Ledger, to be kept by the Accounts Officer, from the establishment pay bills.

11. INVESTMENTS:

All moneys not immediately required for the purposes of the Fund shall from time to time be invested by and held in the name of the Board in securities authorised by the Indian Trust Act, 1882 or in fixed deposits in the State Bank of India or in Nationalised Banks or in such investments as may be approved by Central Government from time to time and the Board may from time to time by the sale of securities, standing in its name or the realisation of fixed deposits raise such sum or sums as may be required for the purpose of the Fund.

12. INTEREST ON INVESTMENTS:

- (a) Interest shall be allowed by the Board on all contributions made by the subscriber, including the amount if any, credited during the course of the year towards proceeds of insurance policy or policies under regulation 13 together with interest thereon actually credited to the subscriber's account respectively at the same rate of interest per annum as that which shall have been earned by the Board during the previous official year upon the Provident Fund investments made under Regulation 11.

NOTE: For purpose of this regulation, the rate of interest shall be rounded off to the nearest quarter percent.

Interest shall be calculated in the following manner, that is to say, the total (excluding fractions of a rupee) of the minimum monthly balances to the credit of each subscriber for the year or for any shorter period necessitated by the closing of an account shall be ascertained and a single months interest for the year and proportionately for any shorter period at the appropriate rate or rates shall be calculated upon such total.

The interest so calculated shall be added to the principal at the end of the official year or at the closing of the account, if closed during the course of a year,

- (b) In the case of subscriber who dies or quits service or retires during the course of a year, interest shall be paid upto the end of the month preceeding that in which payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable, whichever of these periods be less, at the appropriate rate fixed for the previous financial year.

Provided that where the Accounts Officer has personally satisfied himself that the delay in payment was caused by circumstances beyond the control of the subscriber and that administrative delays involved in the matter have been fully investigated and action taken, interest may be paid upto the end of one year after the month in which such amount become payable

In the case of a subscriber who dies and the amount at his credit is not paid due to his nominee being a minor, interest shall be credited to the subscriber's account in accordance with this regulation till the date of payment or upto the end of six months after the month in which the subscriber dies whichever is earlier.

13. PAYMENT TOWARDS INSURANCE POLICIES:

Payment towards insurance policies on mutually agreed terms between the subscriber and the Board shall apply only to subscribers who before the 1st August, 1969 have been permitted for making withdrawals from the funds for payment towards Life Insurance Policies and this facility shall not be extended to any new policy after the 1st August, 1969.

14. INCENTIVE BONUS:

A subscriber to the fund who on 1.4.78 and 1.4.79 and thereafter on 1st April, every year has not withdrawn any amount from his Provident Fund Account during the preceeding five years or three years as the case may be, will be entitled to a bonus at the rate of 1% on the entire balance at his credit on 31.3.78 and 31.3.79 and 31st March, of the preceeding year, thereafter.

NOTE:i) Payment on Bonus interest during 1978-79 the five year period to be taken into account will be the period from 1.4.74 to 31.3.79 and so on.

ii) The period of non-withdrawal is reduced to 3 years commencing from 1st April, 1979.

iii) The term 'withdrawal' means both refundable and non-refundable withdrawals. Withdrawal for financing insurance policies will not make subscribers ineligible for the benefit.

iv) The bonus so calculated will be rounded to the nearest whole rupee (Fifty paise counting as the next higher rupee). This will be credited to the account of the subscriber in addition to the interest of the Provident Fund balances.

v) The bonus will be admissible only when a subscriber has been subscribing to the fund during the preceeding 5 years/3 years except where the rules permit temporary suspension of subscription for a short period e.g. while on leave or under suspension.

vi) The year for the purpose of calculating bonus will mean financial year. But if a subscriber joins the fund or quits service in the middle of a year the year of joining and the year of quitting services will be deemed to be full year.

vii) The amount of bonus will be debited to the Board's Revenue Account.

15. TRANSFER FROM/TO OTHER SERVICES:

A person who has joined the Board's service from the service of any Government, of a Railway Administration or other employer, may, if he becomes a subscriber to the Fund, have any amount standing to his credit in a Provident Fund maintained by the Government, Railway Administration or other employer on the date of his joining the Board's service, transferred to his credit in the Fund. The amount so transferred shall carry interest.

In the event of a subscriber being permanently transferred to the service under a Government, a Railway Administration or any other employer the balance in the Provident Fund account of the subscriber may, instead of being paid in cash, be transferred to his account with the new employer and thereupon these regulations shall cease to apply to him/her.

16. ADVANCES FROM THE FUND:

A temporary advance may be granted to a subscriber, from the amount of subscription together with interest thereon standing to the credit of the subscriber at the discretion of the Chairman subject to the following conditions:

1. PAYMENT OF ADVANCES:

For one or more of the following purposes:-

- (i) Illness: to pay expenses in connection with the illness or confinement or disability of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him.
- (ii) Obligatory expenses: to pay obligatory expenses on a scale appropriate to subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal/marriage, funerals or other ceremonies; of persons actually dependent on him;
- (iii) education: to meet the cost of higher education of the subscriber and members of his family or any person who is actually dependent on him in the following types of cases --
 - a) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the high school stage and
 - b) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is not less than three years.

iv) Legal: to meet cost of legal expenses incurred by the subscriber in the following types of cases:-

- a) Where he takes recourse to legal proceedings to vindicate his position in regard to any allegations made against him in respect of any acts done by him in the discharge of his official duties; or
- b) Where he is prosecuted in a court of law in respect of any alleged official misconduct or where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry.

Provided that no advance shall be admissible

- i) where an employee takes recourse to a court of law in respect of any incidents unconnected with his position as a Board's employee.
 - ii) Where an employee sues the Board in respect of any of his service grievances or against the imposition of any penalty on him.
- (v) Reconstruction - to meet expenses for the reconstruction of huts or houses damaged by cyclone, floods, fire etc.
- (vi) Any other purposes - In special circumstances if the sanctioning authority is satisfied that the subscriber concerned requires the advances for reasons not specified in these regulations and also in cases of acute distress.

2. CONDITIONS FOR PAYMENT OF ADVANCES:

(i) An advance shall not except for special reasons exceed 3 months pay or the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund whichever is less.

NOTE: - The term pay occurring in this Regulation, means emoluments as defined in Regulation 3.

(ii) An advance shall not except for special reasons be granted until at least twelve months after the final repayment of all previous advances.

(iii) When an advance is sanctioned before repayment of last instalment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

17. REPAYMENT OF ADVANCE:

(a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the Chairman may direct but such number shall not be less than 12 unless the subscriber so elects or in any case, more than 36. A subscriber may at his option repay in a smaller number of instalments than that specified above.

Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced if necessary to admit of a fixation of such instalments.

b) Recovery shall be made in the manner provided in Regulation 10 for the realisation of subscriptions and shall commence on the first occasion after the advance is made on which the subscriber draws emoluments, other than leave salary or subsistence grant for a full month. Recovery shall not be made except with the subscriber's consent while he is on leave or in receipt of subsistence grant and may be postponed by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

c) If more than one advance has been made to a subscriber, each advance shall be treated separately for purpose of recovery.

18. WRONGFUL USE OF ADVANCE:

Notwithstanding anything contained in these regulations if the sanctioning authority is satisfied that money drawn as an advance from the Fund under Regulation 16 has been utilised for a purpose other than that for which drawal of the money was originally sanctioned, the amount in question shall, forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default be ordered by the sanctioning authority to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber, even if he be on leave in one or more monthly instalments not exceeding twelve as may be fixed by the sanctioning authority.

NOTE: The term emoluments as used in the regulation does not include subsistence grant.

19. INTEREST ON ADVANCE;

No interest will be credited to the account of any subscriber to whom an advance has been made on any amount for the time being debited to his account as representing an outstanding advance.

20. FINAL WITHDRAWALS FROM THE FUND:

(1) A subscriber may be permitted by the sanctioning authority to make final withdrawals from the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in his/her Provident Fund Account subject to the conditions specified therein.

(A) Housing: During the service of a subscriber for one or more of the following purposes, namely for :

- a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his/her residence including the cost of the site proposed to be acquired from the State Housing Board/Co-operative Building Societies;
- b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his/her residence;

Provided that the amount actually subscribed

by the subscriber along with the interest thereon standing to the subscriber's credit or the actual cost of the house/flat including the cost of the site and for repayment of a loan, if any expressly taken, in that behalf, whichever is less.

c) purchasing a house site for building a house thereon for his/her residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

Provided that the loan was taken not more than twelve months before the date of receipt of the said application

Provided further that the amount of the withdrawal shall not exceed one half of the amount actually subscribed by him along with the interest thereon standing to his/her credit in the Fund, or the actual cost of the site whichever is less.

CLARIFICATION: The actual expenditure incurred in connection with the sale or transfer and execution of deeds may be reckoned as part of the cost of the site.

d) constructing a house on a site purchased under clause (c):

Provided that the amount of withdrawal for the purpose shall not exceed the balance of amount actually subscribed, by him/her together with interest thereon standing to the credit of the subscriber or the actual cost of construction of the house whichever is less.

e) additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber without assistance from the Fund or other Government Sources;

Provided that the amount of the withdrawal does not exceed the cost thereof or the amount actually subscribed by him along with interest thereon or Rs.10,000/- whichever is less.

NOTE:

1. While sanctioning withdrawals under these regulations the sanctioning authority should satisfy himself that the size and the cost of the house/flat/site are not disproportionate to:

- i) the status of the subscriber concerned
- ii) the resources available in his/her provident fund account.
- iii) that the amount is actually required for the purpose of purchasing the house/flat/site or for repayment of a loan expressly taken for the purpose as the case may be, and
- iv) that the subscriber will acquire full title to the house/flat/site proposed to be purchased.

2) Withdrawal under sub-clause (a) or (e) of Clause (A) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

3) Withdrawal under sub-clauses (a), (d) or (e) of Clause (A) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

4) In the case of construction of a house/flat under sub-clause (a) or (d) the withdrawal will be permitted only in equal instalments (not less than two and not more than four in number), the instalments after the first being authorised by the sanctioning authority on the basis of the progress of construction of the house/flat.

5) The construction of the house should be commenced within six months of withdrawal of money and should be completed within a period of two years from the date of the commencement of construction.

The sanctioning authority may, at his discretion, relax the limit of six months prescribed above to one year.

6) If the amount is withdrawn either wholly or partly for the purpose of repayment of a loan previously raised for the purpose of purchasing or redeeming of the house/flat under sub-clause (b) the loan should be liquidated within three months of withdrawal.

7) The withdrawal may be allowed in one instalment in cases of outright purchase of a house site or for repayment of a loan earlier taken for the purpose, and in not more than three instalments if payment for the site is to be made on an instalment basis.

8) The house site shall be purchased within a period of one month of the withdrawal or the withdrawal of the first instalment as the case may be. In fulfilment of this condition, the sanctioning authority may require the production of receipts issued by the seller, the house building society, etc., in token of the amount of withdrawal/instalment having been utilised for making payment towards purchase of the site.

9) A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of works, Housing and supply for the grant of advances for the House Building purposes or has been allowed any assistance in this regard from any other Government or Port Trust Source shall be eligible for the grant of final withdrawal under this regulation for the purpose specified therein:

Provided that the sum withdrawn under this regulation together with the amount of advance taken under the aforesaid scheme or the assistance taken from any other Government Source or Port Trust Source shall not exceed the maximum limit that may be prescribed from time to time under the aforesaid scheme.

10) In the case of acquisition of a house/flat/site from the State Housing Board/Co-operative Building Societies, withdrawal will be permissible of the actual amount subscribed along with interest thereon in order to make:

- i) the initial payment on allotment of a house/flat and
- ii) one lumpsum payment to the housing board later while in service to reduce the instalment dues or to liquidate the balance instalment dues.

In the case of employees who have already paid the initial lumpsum amount from their own private resources one final withdrawal will be allowed to the extent of amount subscribed by them and interest thereon either to reduce the instalment dues or to liquidate the balance instalment dues.

11. The house/flat/site proposed to be acquired or redeemed by the subscriber with the help of the amount withdrawn as aforesaid shall be situated at the place of his/her duty or at his/her intended place of residence after retirement.

12. Withdrawals will be permitted for building, acquisition or redemption of one house or site only:

Provided the employee does not already own a house/site at the place of his/her duty or at his/her intended place of residence after retirement.

13. The subscriber who avails of the above withdrawals shall execute an agreement and submit declarations in the form and manner as may be prescribed and required for the above purpose.

14. Only one withdrawal shall be allowed under this sub-regulation for purposes of housing.

15. The subscriber shall submit a report in the prescribed form to the sanctioning authority on or before the 31st December in each year so long as he is in the Board's service that the house/flat/site remains in his sole ownership and that he has not parted with the possession thereof by way of transfer, sale mortgage gift, exchanges, lease for a term exceeding three years or otherwise howsoever without the previous permission of the sanctioning authority in writing. He/She shall also submit if required, the tax receipts, title deed etc. The amount withdrawn shall become repayable in one instalment with interest thereon at the appropriate rate or rates fixed from time to time under Regulation 12 from the month of such withdrawal by the subscriber, if the house is sold or gifted or exchanged or mortgaged or leased for a term exceeding three years at any time before retirement without the sanctioning authority's previous permission. In default, it shall be ordered by the Sanctioning authority that the amount be recovered from the subscriber's emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments as may be decided by the Sanctioning Authority.

(B) After completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier for one or more of the following purposes:

NOTE: In the case of employees who are admitted to the General Provident Fund, under note to Regulation 2, the service rendered under State or Central Government or Corporate Body owned or controlled by the Government shall count for purposes of final withdrawal under this Regulation.

(a) EDUCATION: for meeting the cost of higher education of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:-

- i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
- ii) for any medical, Engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage; provided that the course of study is not less than three years.

The amount will be limited to 3 months emoluments but in no case shall the amount exceed the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the fund.

The withdrawal will not be permissible more than once every six months.

The subscriber concerned should satisfy the sanctioning authority within a period of six months from the date of withdrawal of the amount that it has been utilised for the purpose for which it was intended.

Notwithstanding the provisions in sub Class (i) and (vi) of sub Regulation (2) of this Regulation, in case where a portion of the money withdrawn by the subscriber is not likely to be spent within six months of the date of withdrawal and the subscriber contemplates making a further withdrawal during the following half year, he may, by notifying in writing to the sanctioning authority, before the expiry of the said period of six months, adjust the excess amount in the proposed withdrawal provided that such excess amount is not more than 10 percent of the amount utilised and action to withdraw further amount is taken within one month of the expiry of six months period.

(b) BETROTHAL/MARRIAGE:

for meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his daughter(s) or his son(s) and any other female/male relation actually dependent on the subscriber.

The amount of withdrawal in respect of each marriage will be the amount actually subscribed by the subscriber along with the interest thereon standing to his credit, or

Ten months' emoluments for daughter/female dependant or six months emoluments for son/male dependant as the case may be whichever is less.

NOTE: i) for the purpose of this Regulation the word 'Marriage' includes 'betrothal ceremony' also.

ii) the betrothal ceremony and marriage ceremony shall be treated as separate purposes. A subscriber who has withdrawn on the occasion of 'betrothal ceremony' is eligible to make another final withdrawal on the occasion of 'marriage ceremony' also.

iii) If two or more marriages are to be celebrated simultaneously, the amount admissible in respect of each marriage will be determined as if the withdrawals are sanctioned separately one after the other.

iv) the withdrawal will be allowed not earlier than three months preceding the month in which the marriage actually takes place.

v) in respect of the same marriage, a subscriber may either withdraw the money in terms of this regulation or draw temporary advance under Regulation 16.

vi) The subscriber should submit a report to the sanctioning authority within a period, of one month from the date of marriage, or if he is on leave, within one month of return from leave, that the money withdrawn has actually been utilised for the purpose for which it was intended.

(C) ILLNESS:

For meeting the expenditure for prolonged illness of the subscriber or any person actually dependant on the subscriber.

The amount of withdrawal will be the amount actually subscribed by the subscriber along with interest thereon standing to the credit of the subscriber or 6 months emoluments whichever is less.

The subscriber should submit a report to the sanctioning authority within a period of one month from the date of withdrawal of the amount that it has been utilised for the purpose for which it was drawn.

PURCHASE OF MOTOR CAR/MOTOR CYCLE/SCOOTER ETC.

After completion of 15 years of service (including the broken periods of service, if any) of a subscriber or 5 years prior to attaining the age of superannuation, withdrawal may be permitted for purchasing a motor car/motor cycle/scooter or for repaying a loan already taken by the subscriber for this purpose, subject to

i) The subscriber's basic pay should be Rs.3,500/-

per month or more in the case of purchase of motor car and Rs.1,500/- per month or more in the case of motor cycle/scooter etc.

ii) The amount of withdrawal is limited to Rs.50,000/- for purchase of motor car and Rs.8,000/- for purchase of motor cycle/scooter etc., or the amount standing to the subscriber's credit whichever is less.

iii) Such a withdrawal shall be allowed only on one occasion.

iv) In the case of withdrawal for purchase of another motor car/motor cycle/scooter, advances for the purpose under the Scheme for purchase of car/motor cycle/ scooter will not be admissible.

v) The motor car/motor cycle/scooter should be purchased within one month of the withdrawal of the money and proof of purchase should be produced to the satisfaction of the sanctioning authority failing which the entire amount is refundable to the fund together with interest at the appropriate rate as fixed under Regulation 12.

vi) The subscriber shall submit a report to the sanctioning authority every year as long as the subscriber is in the Board's service that the motor car/motor cycle/scooter remains in his sole ownership. He shall not sell, mortgage or transfer the car/motor cycle/scooter without the previous permission of the Chairman and in case it is so parted with the amount of withdrawal shall be refunded to the credit of the subscriber's Provident Fund together with interest at the appropriate rate as fixed under Regulation 12.

vii) The subscriber who avails of the above withdrawal shall give an undertaking to the sanctioning authority on a stamp paper in the prescribed form.

D. 90% WITHDRAWAL:

A subscriber may be permitted to withdraw within 12 months before the date of retirement an amount not exceeding 90% of the amount standing to the credit of the subscriber payable to him from the Fund without linking to any purpose.

2. CONDITIONS FOR FINAL WITHDRAWALS:

1) REDEPOSITION:

Any sum withdrawn at any one time for one or more purposes specified under this Regulation from the fund which is found to be in excess of that actually required by the subscriber/unutilised for the purposes should be redeposited forthwith into the Fund together with the interest due thereon at the appropriate rate or rates fixed from time to time under Regulation 12.

(ii) REPAYMENT:

A subscriber who has been permitted to withdraw the money from the fund at any one time for one or more purposes under this Regulation shall satisfy the sanctioning authority within the specified period, that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof has not been applied for the purpose for which it was withdrawn, shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from subscriber's emoluments either in one lumpsum or in such number of instalments as may be determined by the sanctioning authority.

(iii) The subscriber shall execute agreements, submit declarations and produce documentary evidences appropriately as required for the amount withdrawn for one or more purposes under these regulations in the manner and form as may be prescribed and directed by Chairman.

3. CONVERSION:

Any outstanding balance against the temporary advances drawn for the purpose, aforesaid under Regulation 16 may, at the written request of a subscriber, be converted into a final withdrawal under this regulation provided he had on the date of such drawal satisfied the conditions mentioned therefor.

21. CLOSING OF ACCOUNTS & PAYMENTS:

(1) The account of each subscriber shall be closed and the amount standing to his credit in the fund shall become payable on his quitting service -

i) when he is dismissed/resigns

Provided that a subscriber who has been dismissed/resigned from service, is subsequently reinstated in service shall if required to do so by the Board, repay to the Accounts Officer for credit to his account any amount paid to him with interest at the rate provided in Regulation 12.

ii) when he retires on superannuation or has been permitted to retire under the Madras Port Trust Employees (Retirement) Regulations or has been declared by the Trust's Chief Medical Officer as unfit for further service; or

iii) when he dies.

(2) PAYMENT ON DEATH OF A SUBSCRIBER:

(a) when the subscriber leaves a family -

i) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of regulation 6 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

- ii) If no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares.

Provided that no share shall be payable to -

1. sons who have attained legal majority.
2. sons of a deceased son who have attained legal majority.
3. married daughters whose husbands are alive, and
4. married daughters of a deceased son whose husbands are alive, if there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided also that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso;

NOTE: Any sum payable under these regulations to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of Section 3 of the Provident Fund Act, 1925.

b) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of Regulation 6 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the fund or part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

NOTE: 1) when a nominee is dependant of the subscriber as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Fund Act, 1925, the amount vests in such nominee under sub-section 2 of Section 3 of that Act.

2) When the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 6 subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the fund, the relevant provisions of clause (b) and of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 4 of the Provident Fund Act, 1925 are applicable to the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate.

(3) when a nominee is not a dependant of the subscriber as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Fund Act, 1925, the amount if it does not exceed Rs.10,000/- shall be paid to the nominee and if the amount exceeds Rs.10,000/- it shall be paid to the nominee only on production of succession certificate, probate, or letters of administration.

(c) WHEN THE SUBSCRIBER LEAVES NOMINEES WHO ARE MINORS:

In the case of subscriber who dies and one or more of whose nominees to the fund is a minor or are minors at the time of the subscriber's death the share due to the minor(s) shall be paid

a) to the guardian of the minor(s) appointed by the Court of Law

Provided that the Provident Fund money to the extent of Rs.10,000/- (or the first Rs.10,000/- where the amount payable exceeds Rs.10,000/-) on behalf of the minor(s) can be made to his/their natural guardian or when no natural guardian exists, to the person considered fit by the Chairman to receive payment on behalf of the minor(s), without requiring him to produce a guardianship certificate. The person receiving payment on behalf of the minor/minors should be required to execute a bond signed by two sureties agreeing to indemnify the Board against any subsequent claim. The balance in excess of Rs.10,000/- if any shall be paid according to law.

Provided further that in cases where the natural guardian is a Hindu widow or Hindu Widower, the payment of Provident Fund moneys on behalf of her or his minor children shall be made to her or him as the case may be irrespective of the amount involved without production of guardianship certificate or any indemnity bond unless there is anything concrete to show that the interests of the mother or the father, as the case may be are adverse to those of the minor children.

It is essential, however, that in the absence of a natural guardian there should be adequate 'prima facie' grounds for making payment to the person claiming it. Such ground can exist only if he/she is shown by a sworn affidavit to be a de-facto guardian and his/her bonafides have been ascertained. Even if a guardian has not yet been appointed by the Court, if the minor and his property are in the custody of some person such person is in law a de-facto guardian. The person who comes forward to claim payment on behalf of the minor should satisfy the Chairman by an affidavit that he is in charge of the property of the minor and is looking after it, or that if the minor has no property other than the Provident Fund money, the minor is in his custody and care. The affidavit is to be produced in addition to the indemnity bond with suitable sureties; or

(b) to the nominee when the amount is claimed by the nominee after he or she has attained majority.

Provided that in every case interest shall be allowed in accordance with the note to regulation 12(b) till the date of payment or to the end of sixth month after the month in which the subscriber dies whichever is earlier."

22. CREDITING TO REVENUE ACCOUNT:

All balances of Provident Fund unclaimed for more than three complete account years will, at the end of each year be credited to the Board's Revenue Account.

A sum credited to the Board's Revenue Account cannot, without the sanction of the Board, be refunded to the person or persons who could have drawn it any time before its credit to the Revenue Account.

23. ASSIGNMENT OF POLICY:

i) If the person to whom, under these regulations, any amount or policy is to be paid, assigned, re-assigned or delivered is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or reassignment or delivery will be made to such manager and not to the lunatic.

ii) In case where no Manager for the estate of the lunatic has been appointed, the payment or re-assignment of the policy may be made in terms of Section 95(1) of the Indian Lunacy Act to the person having charge of the Lunatic under the orders of the Collector. The Chairman of the Board shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the Lunatic and the balance, if any or such part thereof as he thinks fit, is to be paid for the maintenance of such members of the lunatic family as are dependent on him for maintenance. But before this is done, the person to whom the payment becomes payable under the rules will have to be certified by the Magistrate as Lunatic.

24. PROCEDURE FOR PAYMENT:

The procedure for payment of the amount standing to the credit of the subscriber, execution of bonds, agreements, submission of declaration and production of documentary evidences appropriately as may be required for the purposes under these regulations shall be in the manner and forms as may be prescribed by Chairman from time to time.

25. INTERPRETATION:

If any question arises relating to the interpretations of these regulations, the ~~Chairman~~ ^{Chairman shall} ~~be guided by~~ ^{Some will be decided by the Board.}

26. APPLICATION OF GOVERNMENT RULES:

In applying the provisions of these regulations and in matters not dealt within these regulations, the orders and decisions of the Government contained in Government's 'General Provident Fund (Central Services)

Rules' shall subject to such exceptions and modifications as the Board may decide from time to time, the adopted with the prior approval of the Central Government pending formal amendment to these regulations.

27. REPEAL AND SAVING:

On commencement of these regulations, the Madras Port Trust Regulations relating to Provident Fund and Gratuity which were in force immediately before these regulations come into force shall cease to have any effect.

Provided that any order made or action taken or liberalisation allowed under the provisions of the repealed regulations shall be deemed to have been made or taken or availed of under the corresponding provisions of these regulations.

- - - - -

S C H E D U L ESANCTIONING AUTHORITY FOR THE PURPOSE OF THE MADRAS PORT TRUSTGENERAL PROVIDENT FUND REGULATIONS - REGULATION NO. 3

Regulation Number	Description of powers delegated.	Authority to which the power is delegated.
13.	The Board's Power to sanction applications from subscribers to the Board's Provident Fund for permission to utilise the subscription to the fund towards the payment of premium on policies of Life Assurance.	Chairman
16.	The Board's powers to grant temporary advance to the Provident Fund Subscribers from the amount standing to his/her credit.	
	Chairman ..	Full powers in the case of all employees including Heads of Departments
	Deputy Chairman ..	Full powers in the case of all employees excluding Heads of Departments.
	Heads of Departments ..	Full powers in the case of Classes I & II and Classes III & IV employees of their departments.
(Cases involving relaxation will require the sanction of Deputy Chairman/Chairman).		
20.	Final withdrawal from Provident Fund.	Chairman: Full powers in the case of employees including Heads of Departments. Deputy Chairman: Full powers in the case of employees excluding Heads of Departments.
22.	The Board's power to sanction payment to these concerned from the Revenue account of sums credited thereto viz. balances of Provident Fund unclaimed for more than three complete account years.	Chairman

FOIA b 7 - NECESSARY

SCHEDULE REFERRED TO IN REGULATION 6 OF THE
MADRAS PORT TRUST GENERAL PROVIDENT FUND
REGULATIONS

Account No.

'I - - - - - hereby nominate
the person(s) mentioned below who is/are member(s)/non-member(s) of my
family as defined in the Madras Port Trust General Provident Fund
Regulations to receive the amount that may stand to my credit in the
Fund as indicated below, in the event of my death before that amount
has become payable or having become payable has not been paid.

1	2	3	4	5	6	7
Name and full address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber.	Age of the nominee.	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid.	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber.	If the nominee is not a member of the family as provided in Regulation 3 indicate the reasons.

Dated this day of 19, . . . at

Signature of the subscriber

Name in Block letters

Designation

Two witnesses to signature

Signature:

Name and address.

1.

2.

(For use by the Accounts Department)

ACCEPTED

FINANCIAL ADVISER AND CHIEF ACCOUNTS OFFICER.

- (a) Your name may be filled in.
- (b) Name of the fund may be completed suitably.
- (c) Definition of term "family" as given below:

Family means -----

- (i) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent;

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these Regulations relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

- (ii) in the case of a female subscriber, the husband, parents, child, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent;

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE: 'Child' means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber who lives with the employee and is treated as a member of the family and to whom the employee has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

- (d) Col.4. If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.
- (e) Col.5. Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.
- (f) Col.6. Do not mention your name.
- (g) Draw line across the black space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

[F No. PR-12016/9/96-PE-II]

K. V. RAO, Under Secy.

